

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्की,  
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० - 26/2023

प्राप्त : -  
श्री बलराम पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी साकुआना तहसील टिब्की जिला हनुमानगढ़ :

प्रार्थी

बनाम

विजय कुमार पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी साकुआना तहसील टिब्की जिला हनुमानगढ़ व  
रामकुमार पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी साकुआना तहसील टिब्की जिला हनुमानगढ़ ।  
तहसीलदार राजस्व टिब्की ।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रार्थी  
अब्दुल सतार जोईया अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 5/2/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चकनं० 1 एसबीएन के खातासं० 132/136 में  
ल 4364 है० में से प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक का 569/6546 हिस्सा व प्रतिवादीसं०  
4,5 प्रत्येक का 127/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 6 का 185/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं०  
का 1015/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 8, 9, 12 प्रत्येक का 63/2182 हिस्सा व प्रतिवादी  
सं० 10 का 169/1091 हिस्सा व प्रतिवादीसं० 11 का 169/2182 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 13  
का 253/4364 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थनापत्र है।  
प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थी का 569/6546 हिस्सा आराजी संयुक्त खाता में  
प्रार्थीगण सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 के साथ दर्ज है। प्रार्थी अपने हक व  
हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के हक व  
हिस्सा की आराजी अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 के साथ संयुक्त दर्ज रहने से प्रार्थी  
अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा  
काशत के समय सीमा का विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपनी आराजी का खाता  
प्रार्थीगणसं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगणसं० 3 ता 13 के साथ संयुक्त नहीं रखना चाहता है व  
प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता की आराजी में से अपने 569/6546 हिस्सा की  
आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम  
करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं० 1 व 2 जो कि प्रार्थी के सगे भाई है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 में  
दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 व प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 के नाम से संयुक्त खाता में

दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 की आराजी संयुक्त खाता दर्ज चली आ रही है लेकिन अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 जो कि बिना खाता विभाजन करवाये संयुक्त खाता की आराजी में से अपने हिस्सा की आराजी में से अच्छी अच्छी भूमि को रहन, बैय करने पर आमादा है तथा बार बार प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हम आज कल में अपने हिस्सा की आराजी को बैचान कर देवेगें व उक्त भूमि का कब्जा दिगर व्यक्तियों को देवेगें तथा भूमि बैचान करने की बात भी हमने गाँव के किसी व्यक्ति से कर ली है, अगर अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 अपने इस गलत व विधि विरुद्ध कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। उक्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णाय क्षति, तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अर्द में हल्फनामा प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 इस अर्द की जारी की जावे कि चकनं० 1 एसबीएन के खातासं० 132 / 136 में कुल 4.364 है० में से अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक अपने 569 6546 हिस्सा की आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि चकनं० चक 1 एसबीएन के खाता सं० 132/136 में कुल 4.364 हैक्टेयर आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में अपने 569/6546 हैक्टेयर आराजी को रहन बैय व अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने से निषेद्ध रहे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होने के पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल सतार जोईया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि दरखास्त की दफा 1 में दर्ज तथ्य कि अनवान सदर का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज किये गये है, स्वीकार नहीं। वादी द्वारा पेश वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिज खारीजी के है। दरखास्त की दफा 2 में वणित आराजी मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। दरखास्त की दफा 3 में वर्णित कथन कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थी का 569 / 6546 हिस्सा संयुक्त खाता में अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं० 3 ता 13 के साथ दर्ज होने तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, का कथन स्वीकार है, बाकी कथन कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज किये है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा प्रतिवादी सं० 3 ता 13 अरसा दराज से अपने अपने हक व हिस्सानुसार काबिज रहकर अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण ने अपने हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की आराजी में काफी सुधार किया है, इसलिए प्रार्थी अच्छी मन्दी के लिहाज से बटवारां करवाने का कतई अधिकारी नहीं है जबकि प्रार्थी हक हिस्सा व कब्जा काश्त के गवाबिका खाता विभाजित करवाकर, अलग से कायम करवाने का अधिकारी है। दरखास्त की

11 4 में दर्ज कथन कि अप्रार्थी सं० 1 व 2 जो कि प्रार्थी के समे आई है तथा प्रार्थना पत्र की  
 11 2 में दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 व प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 के नाम से संयुक्त  
 ता में दर्ज है, का कथन स्वीकार है। बाकी कथन कतई मालत, असलत व समझकर दर्ज  
 ये गये है, स्वीकार नहीं। दफा हाजा में दर्ज कथन कि अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 जो कि बिना  
 ता विभाजन करवाये, संयुक्त खात की आराजी में से अपने हिरसा की आराजी में से अपनी  
 धी भूमि को रहन, बैय करने पर आमादा है तथा बार बार प्रार्थी को एलर्जिया कमकी है यह  
 कि आज कल में ही अपने हिरसा की आराजी को बैयान कर देंगे, क सम्बन्ध में निवेदन है  
 11 अप्रार्थीगण अपने हक व हिरसा की आराजी पर काबिज रहकर कश्त करते गये जा रहे है  
 11 अप्रार्थीगण अपने हिरसा की सीमा तक विवादित भूमि के स्वामी है। संयुक्त सम्पत्ति के  
 11 भी सह-अंशधारी कब्जे में होना माने जाते है व अप्रार्थीगण सह- स्वामी है तथा बिना विभाजन  
 के अपने हिरसे की सम्पत्ति को विक्रय करने के हकदार है। विधि के मुताबिक सह- खातेदारी  
 की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए किसी सहखातेदार  
 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का  
 सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अदालत हाजा द्वारा जारी एक  
 पक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है तो अप्रार्थीगण अपने विधि व  
 खातेदारी अधिकारों से महरूम रह जावेगे तथा हम अप्रार्थीगण को अपरिमय क्षति होगी, ताईद  
 में हल्फनामा पेश है। अतः दरखास्त 212 जबाब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मंत्र शब्द  
 पत्र पेश कर निवेदन है कि अदालत हाजा द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 22.03  
 2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आर. टी. ए. खाशीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
 मुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों का महन अध्ययन करने के उपरान्त  
 इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि वास्तव घोषणा साक्ष्य सबूतों के आधार पर मूल दावे  
 के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित  
 नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के  
 दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा  
 अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अदस्तावेज से  
 जाहिर होता है कि उक्त वादभूमि चक 1 एसवीएन के खाता सं० 132/136 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण  
 सहखातेदार की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार  
 वाद भूमि में प्रार्थी अपने हक हिरसे अनुसार खाता तकसीम की मांग कर रहा है जो की वाद से  
 साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि में किसी अपने हक व हिरस का  
 अच्छी एवं मंदी अनुसार खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है या नहीं। उपरोक्त निवेदनस्वरूप  
 प्रार्थी केवल अपने हिरसे तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।  
 प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष में

रहा है। जब तक प्रार्थी की आराजी का अच्छी मंदी अनुसार निर्धारण नहीं हो जाता तब  
अप्रार्थीगण को उक्त वाद भूमि में अपने हिरसा की हद तक रहन बैय करने से पाबन्द किया  
ना न्यायोचित नहीं है क्यों कि सयुक्त खाता की भूमि में अप्रार्थी केवल अपने हक व हिस्से  
वेचान करेगा न कि विशेष किलो का विधि के मुताबिक सह- खातेदारी की प्रत्येक इय भूमि  
प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए किरती सहखातेदार को अपने हक व  
से तक की भूमि को रहन बैय हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायालय के  
भिमत् में न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला  
प्रार्थीगण के पक्ष में बनाता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दिनांक 22.03.2023  
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक... 5/2/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया  
या।

  
(सहायक सचिव R.A.S.)  
उपसहायक सहायकरी (राजस्व)  
एवं सहायक कैलक्टर  
टिब्बी